

#### ग्रसाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II--- खण्ड 3--- उपलण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

### माधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 16] नई दिल्ली, मंगलबार, जनवरी 30, 1968/माघ 10, 1889

No. 16] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 1968/MAGHA 10, 1889

# इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह झलग संकलन के क्य में रका जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

# MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Agriculture)

Land Acquisition Review Committee

The following translation in Hindi of the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963).

SARAN SINGH, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास श्रीर सहकार मंत्रालय

(कृषि विभाग)

लैंड एक्वीजीशन (कंपनीज) रुत्स, 1963 का हिन्दी में निन्मलिखित श्रनुवाद राष्ट्रपति क मधिकार के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है श्रीर राजभाषा श्रिधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के श्रधीन हिन्दी में उनका प्रमा-णिक पा समझा जाएगा।

## नई दिल्ली, 22 जून, 1963

सा ० का ० निं ० 2 34—मूमि ग्रर्जन ग्रिधिनियम, 1894 (1894 का श्रिधिनियम सं ० 1) की धारा \$5 द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के तथा केन्द्रीय सरकार के ग्रौर राज्य सरकारों के ग्राफिसरों के मार्गंदर्शन के लिये निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाती है, ग्रर्थात् :—

- 1— संक्षिप्त नाम ग्रीर क्षागू होना (1) ये नियम भूमि ग्रर्जन (कम्पनियां) नियम, 1963 कहे जा सकोंगे।
- (2) ये नियम श्रिधिनियम के भाग 7 के श्रिधीन सब कम्पनियों के लिये भूमि के श्रिजन को लागू होंगे।
  - 2 -परिभावएं--इन नियमों में--
    - (i) "श्रधिनियम" से भूमि श्रर्जन श्रुधिनियम, 1894 (1894 का श्रधिनियम सं ० 1) श्रभिनेत है, श्रीर
    - (ii) "सिमिति" से नियम 3 के अधीन गठित भूमि अर्जन सिमिति आभिप्रेत है।
- अधिनियम के भाग 7 के अधीन भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में समुचित सरकार को सलाह देने के प्रयोजन के लिये, समुचित सरकार, शासकीय राजपत्न में अधि-सूचना द्वारा एक समिति गठित करेगी जो भूमि अर्जन समिति कहलायेगी।
  - (2) समिति में निम्नलिखित होंगे,---
  - (i) राजस्व, कृषि श्रौर उद्योग के विभागों के सरकार के सन्धिव या उक्त हर एक विभाग के ऐसे श्रन्थ आफिसर जिन्हें समुचित सरकार नियुक्त करे; श्रौर
  - (ii) ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें समुचित सरकार नियुक्त करे, ऐसी अविधि के लिये, जिसे अह सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
- (3) समुजित सरकार सिमिति के सदस्यों में से एक को उसका सभापति होने के लिये नियुक्त करेगी।
  - (4) समिति प्रानी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी।
- (5) अधिनियम के भाग 7 के अधीन भूमि के अर्जन से सम्बन्ध और उद्भूत होने वाले सब मामलों पर, जिंन पर उससे परामर्श किया जाए, समुक्ति सरकार को सलाह देना और उस तारीख से जिसको उससे परामर्श किया जाए एक मास के भीतर अपनी सलाह निविद्य करना, समिति का कर्त्तव्य होगा।

परंशु समुचित सरकार, समिति द्वारा इस निमित्त प्रार्थना किए जाने पर भ्रौर प्रमृद्धि कारणों के लिथे, उनत कालावधि का विस्तार दो मास से भ्रनधिक की भ्रातिरिगत कलावधि के लिए कर तकेगी।

- 4— मर्जन कार्यवाही भारस्भ करने से पूर्व कुछ मामलों की वावत समुखित सरकार का समाधान किया जाना——(1) जब कभी कोई कम्पनी किसी भूमि के प्रर्जन के लिये समुचित सरकार को भावेदन करे, वह सरकार कलन्टर को निदेश देगी कि वह उसे निम्नलिखित मामलों पर रिपीर्ट प्रस्तुत करे, भ्राथीत्
  - (i) कि करनाति उत्तपरितेत में प्रार्गन के प्रयोजन के लिये उपयुक्त भूमियों का पता लगाने के लिए प्राप्ता पर्शीतम प्रयश्न किया है
  - (ii) कि कम्पनी ने हितबद्ध व्यक्तियों से बातचीत करके ऐसी भूमियों को, युक्तियुक्त कीमत का संदाय करके प्राप्त करने के सब युक्तियुक्त प्रयत्न किए हैं ग्रौर ऐसे प्रयत्न ग्रासफल हुए हैं;
  - (iii) कि प्रार्जित की जाने के लिए प्रस्थापित भूमि उस प्रयोजन के लिये उपयुक्त है;
  - (iv) कि प्रजित की जाने के लिए प्रस्थापित भूमि का क्षेत्र प्रत्यधिक नहीं है;
  - (v) कि कम्पनी भूमि को शीघ्र उपयोग में लाने की स्थिति में है; श्रौर
  - (vi) जहां द्वर्णित की जाने के लिये प्रस्थापित भूमि द्वरूखी कृषि-भूमि हो बहा उस भूमि को द्वर्णन से बचाने के लिये कोई ग्रानुकल्पिक उपयुक्त ग्रास्थांन नहीं मिल सकता।
- (2) कलक्टर कम्पनी को इस निमित्त कोई अभिनेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उन मामलों की जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट है, जांच करेगा और ऐसी जांच करते समय, बह--
  - (i) ऐसी किसी दशा में जिसमें कि ऋजित की जाने के लिए प्रस्थापित भूमि ऋषि-भूमि हो, जिले के ज्येष्ट ऋषिक श्रांफिसर से परामर्श करेगा, चाहे ऐसी भूमि श्र•छी ऋषि≞भूमि हो या न हो,
  - (ii) शिक्षिनियम की धारा 23 श्रीर 24 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए प्रतिकर की लगभग रक्तम भवक्षारित करेगा जिसका उस भूमि के सम्बन्ध में संदेय होना सम्भाव्य है जो कि कलक्टर की राय में कम्पनी के लिये श्रीजित की जानी चाहिए: श्रीर
  - (iii) यह अभिनिश्चित करेगा कि क्या कम्पनी ने अजित की जाने के लिए प्रस्थापित भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों को युक्तियुक्त कीमत (जो ऐसे अवधारित प्रतिकर से कम न हो) प्रस्थापित की।
  - स्पव्टीकरण—-इस नियम के प्रयोजन के लिये, ''श्रव्ही कृषि-भूमि' से कोई ऐसी भूमि श्रमिप्रेत हैं जो उसक्षेत्र के जिसमें वह ग्रवस्थित हो, कृषि-उत्पादन के स्तर श्रीर फसल के पैटर्न पर विचार करते हुए, श्रौसत या श्रोसत से ग्रधिक ।उत्पादिता वाली है श्रौर उद्यान-भूमि या बाग-भूमि इसके श्रन्तर्गत श्राती है।
- (3) उपनिश्म (2) के श्रधीन जांच करने के पश्चात् यंथाशंक्यशी हां कलक्टर समुचित सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा श्रीर उस सरकार द्वारा उसकी एक प्रति समिति को भेजी जाएगी।•

- (4) समुचित सरकार द्वारा श्रिधिनियम की धारा 6 के श्रिधीन कोई घोषणा तब तक नहीं की आएगी जब तक कि----
  - (i) समुचित सरकार ने सिमिति से परामर्श न कर लिया हो श्रौर इस नियम के श्रधीन निवेदित की गई रिपोर्ट पर श्रौर श्रधिनियम की धारा 5 क के श्रधीन यदि कोई रिपोर्ट निवेदित की गई हो तो उस पर विचार न कर लिया हो, श्रौर
  - (ii) श्रिधिनियम की धारों 41 के श्रिधीन करार कम्पनी द्वारा निष्पादित न कर दिया गया ही।

5——बारा 41 के बारीन करार में उपबन्धित की जाने वाली बारें (1) प्रधिनियम की धारा 41 में निर्दिष्ट करार के निबन्धनों के बार्त्तर्गत निम्नलिखित बातें होंगी, अर्थातु—

- (i) कि कम्पनी भूमि का प्रयोग, किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जो उससे भिन्न हो जिस के लिए भूमि ऋजित की गई है, समुजित सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय नहीं करेगी:
- (ii) कि वह समय, जिसके प्रादर निवासगहों या प्रत्यक्षतः तत्संसक्त सुख-सुविधान्नों का परिनिर्माण या उपबन्ध प्रायवा निर्माण या संकर्म का सिन्नमीण या निष्पादन किया जाएगा, कम्पनी की भूमि के प्रस्तरण की तारीख से तीन वर्ष से प्रधिक नहीं होगा:
- (iii) कि जहां समुचित सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह प्रावश्यक समझे समाधान हो जाता है कि कम्पनी निवासगृहों या सुख-सुविधामों प्रथवा किसी निर्माण या सकर्म का परिनिर्माण, उपबन्ध, सिन्नमीण या निष्पादन करार में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर करने से ऐसे कारणों से निवारित हो गई थी जो उसके नियंत्रण के बाहर थे, यहां समुचित सरकार तत्प्रयोजनार्थ समय का विस्तार ऐसी फालावधि से जो किसी एक समय पर एक वर्ष से अधिक न हो, इस प्रकार कर सकेगी कि विस्तार की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी;
- (iv) कि यदि कम्पनी करार में उपवन्धित गतों में से किसी का भंग करे, तो समुचित सरकार कम्पनी की भूमि का भन्तरण वा तिल और भून्य चौषित करने वाला, जिस से कि भूमि समुचित सरकार को प्रतिवर्तित हो जाएगी, भौर यह निदिष्ट करने वाला आदेश दे सकेगी कि श्रिधिनियम की धारा 41 के खण्ड (1) के श्रिधीन अजन के खर्च के रूप में समुचित सरकार को कम्पनी द्वारा सदत रक्षम की एक चौथाई से भ्रमधिक रक्षम नुकसानी के रूप में समुचित सरकार को समपहृत कर दी जाएगी और भ्रतिशेष कम्पनी को वापस कर दिया जाएगा भौर ऐसे दिया गया आदश भ्रन्तिम और आवदकर होगा;
- (v) कि यदि कम्पनी भूमि का भाग मान्न उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाती है जिसके लिए वह प्रजित की गई थी प्रौर समुचित सरकार का समाधान हो जाता है कि यदि उसका उपयोग में न लाया गया भाग पुनगृहीत कर लिया जाए, तब भी कम्पनी प्रभने द्वारा उपयोग में लाए गए भूमि के भाग का उपयोग जारी रख सकती है तो समुचित सरकार एक प्रादेश कर सकेगी जिसमें यह घोषणा हो कि भिम का

उसके उपयोग में न लाए गए भाग की बाबत अन्तरण बालित और शून्य है जिस पर ऐसे उपयोग में न लागा गया भाग समुचित सरकार को प्रतिवर्तित हो जाएगा, और यह आदेश हो कि अधिनयम की धारा 41 के खण्ड (i) के अधीन अर्जन के खर्च के रूप में कम्पनी द्वारा संदत रकम के ऐसे भाग की, जो कि उपयोग में न लाए गए भाग से सम्बन्धित माना जा सकता है, एक चौथाई से अन्धिक रकम नुकसानी के रूप में समुचित सरकार को समपहृत हो जाएगी और उस भाग का अतिशेष कम्पनी को वापस कर दिया जाएगा और ऐसे दिया गया आदेश, खण्ड (vi) के उपबन्धों के अध्यधीन, अन्तिम और आवदकर होगा।

- (vi) कि जहां भूमि के उपयोग में न लाए गए भाग से सम्बद्ध की जा सकते वाली रकम के बारे में कोई विवाद हो, वहां ऐसा विवाद उस न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसकी ब्रधिकारिता के भीतर भूमि या उसका कोई भाग ब्रवस्थित है और उस पर उस न्यायालय का विनिश्चय ग्रंतिम होगा।
- (2) जहां कम्पनी करार के निबन्धनों में से किसी का भंग करती है, वहां समृचित सरकार, उपनियम (1) के खण्ड (iv) या खण्ड (v) के प्रधीन प्रावेश तब तक नहीं देगी, जब तक कि कम्पनी को उस मामले में सुने जाने का प्रकसर न दिया गया हो।
- (3) समुचित सरकार, उपनियम (1) के खण्ड (i) के प्रधीन कोई मंजूरी देने या खंड (iii) के ग्रधीन समय का विस्तार करने या उस उपनियम के खंड (iv) या खण्ड (v) के ग्रधीन कोई मादेश देने से पूर्व, समिति से परामर्श करेगी।

### 6. ग्रतिरिक्त बातें जो धारा 41 के भवीन करार में उपविकास की जा सकेगी---

(1) "नियम 5 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ग्रधिनियम की धारा 41 में निविष्ट करार के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें भी हो सकेंगी, श्रथात्—

"कि म्रात्ययिकता के किसी मामले में जहां म्रधिनियम की धारा 11 के म्रधीन भ्रधिनिर्णय दिए जाने से पूर्व धारा 17 के म्रधीन किसी भूमि का कब्जा लेने की प्रास्थपना है, वहां कम्पनी (नियम 4 के उपनियम (2) के खंड ( ) के म्रधीन भूमि की बाबत यथा म्रवधारित संदेय प्रतिकर की लगभग रकम के दी तिहाई से म्रनधिक) ऐसी रकम भीर ऐसे समय के भीतर जो कलक्टर इस निमित्त विनिधिष्ट करना ठीक समझे ब्याज से मुक्त कलक्टर के पास निक्षिष्त करेगी।"

- (2) जहां उपनियम (1) के अधीन कोई रकम कलक्टर के पास निक्षिप्त की गई हो, वहां कलक्टर ऐसे निक्षिप्त की गई रकम का सदाय उन हितबढ़ क्यक्तियों को निविद्य करेगा, जो कलक्टर की राय में अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर का संवाय प्राप्त करने के हकदार हैं, और जब तक कि अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में विणित आकस्मिकताओं में से किसी एक या अधिक द्वारा निवारित न हो, उसे उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन देगा, अर्थात्—
  - (i) हर एक प्राप्तिकर्ता द्वारा इस करार का निष्पादन कि उस द्वारा प्राप्त की गई रकम श्रांतम रूप से प्रधिनिर्णीत प्रतिकर के प्रति समायोजित की जायगी भौर कि जहां उस द्वारा प्राप्त रकम श्रांतिम रूप से प्रधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम से प्रधिक हो, वहां प्रधिक रकम उससे भराजस्थ के बाकाया के रूप में वसूलीय होगी भौर कि वह इस उपनियम के प्रधीन प्रपने द्वारा प्राप्त रकम की बाबल श्रक्षिनियम के उपबन्धों के श्रशीम किसी ब्याज के लिए दावा नहीं करेगा, श्रीर

- (ii) हुर एक प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिभूति के सहित या रहित जैसा कि कलक्टर विनिध्वित करे एक बन्धपत्र का निष्पादन जिसमें कि प्रतिकर या उसके भाग के लिए किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा किसी वाने के विक्शाफ समुचित सरकार की क्षतिपूर्ति करने का वचनबद्ध हो।
- (3) यधि उपनियम (1) के प्रधीन कम्पनी द्वारा निक्षिप्त की गई रक्षम या उसका कोई भाग उपनियम (2) के प्रधीन संदत न किया जाए, तो कलक्टर यथासाध्यशी घंता से उसे कम्पनी को वापस कर देगा।
- 7. कालिक रिपोटों का निवेदित किया जाना यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि कम्पनी द्वारा निष्पादित करार में उपबन्धित गतों का प्रनुपालन किया जाता है, समुचित सरकार कलक्टर को या ऐ से प्रन्य श्राफिसर को, जिसे वह सरकार तत्प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, निवेश दे सकेगी कि वह उन गतों को जिनका अनुपालन किया गया हो या न किया गया हो तथा उन कार्यवाद्यों को जो कम्पनी द्वारा उनके अनुपालन के प्रति की गई हों, उपदिशत करने वाली एक कालिक रिपोर्ट, ऐसे समय के अन्तरालों पर जो वह विनिदिष्ट करे उसे और समिति को निवेदित करे।
- 8. इति जिनके प्रधीन भूमि के अन्तरण के लिये मंजूरी दी जा सकेगी.—जहां कि कोई कम्पनी जि उसे लिए भूमि प्रधिनियम के श्रधीन श्रजित की गई हो उस भूमि या उसके किसी भागके विकय, दान, पट्टे द्वारा या प्रन्यथा श्रन्तरण के लिए समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी के लिए श्राबंदन करें, वहां ऐसी कोई मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ——
  - (i) नित्रासपूहों, सुख-सुत्रिधात्रों, निर्माणों या सकर्म सहित, यदि कोई हों, भूमि का प्रस्थापित प्रन्तरण किसी प्रन्य कम्पनी को न हो या जहां कम्पनी कोई सहकारी सोसाइटी है वहां ऐसा अन्तरण इसके किसी सदस्य या सभी सदस्यों को न हो, प्रयक्ष
  - (ii) जहां भूमि कम्पनी द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए निवास गृहों के परिनिर्माण के लिए ही अजित की गई हो, वहां निवासगृहों सहित, यदि कोई हों, भूमि का अन्दर्श एसे कर्मकारों को या उनके आश्वित कारिसों को नहीं;

परन्तु ऐसी कोई मंजूरी देने से पूर्व, समुचित सरकार समिति से परामर्श करेगी।

- 9. कुछ कम्पिनयों के सम्बन्ध में विशेष उपजन्ध——(1) जब कि केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण धीन कम्पनी से भिन्न किसी कम्पनी द्वारा किसी भूमि के अर्जन के लिए समुचित सरकार को आवेधन किया जाए, तो ऐसा अर्जन मामूली तौर से अधिनियम के भाग 7 के उपजन्धों के अनुसार किया जाएगा।
- (2) जहां कि केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामिस्वाधीन या नियंद्वणधीन कम्पनी से भिन्न किसी कम्पनी के लिए किसी भूमि को ग्रांजित करने की प्रस्थापना है, बहां समृष्ति सरकार को ग्राधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियां तब तक प्रयोक्तब्य नहीं होंगी जब तक उसका समाधान न हो जाए कि ऐसा करना जीवन या सम्पति को खतरे से बचाने के लिए धावक्यक है या वैसा करना ग्रान्यथा लोकहित में भावश्यक है।
- 10. निरसन-ग्रिधिनियम के भाग 7 के ग्रिधीन, कम्पिनियों के लिए भूमि के ग्रर्जन की बाबत ग्रिपने ग्राफिसरों के मार्गधर्मन के लिए समुचित सरकार द्वारा बनाए गए ग्रीर इन नियमों के प्रारम्म से भन्यवहित पूर्ण प्रवृत सब नियम बहुां तक जहां तक कि वे विरुद्ध हों, प्रभावी नहीं रहेंग ।

शरएसिंह, संयुक्त सचिव ।